



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

त. 288]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 1990/कार्तिक 25, 1912

No. 288]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 1990/KARTIKA 25, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1990

(मंद्रा ओ-17011/5/82-भी.एफ.एस.) भारत सरकार  
ने 17 जून, 1985 की अपनी अधिगूचना संख्या ओ-  
17011/3/78-जी.ओ.पी. द्वारा केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति  
योजना की मानवी पंचवर्षीय योजना में 1-4-1985 से  
31-3-1990 तक की अवधि के लिए पंचम घरण के रूप  
में जारी रखना अधिसूचित किया था, ताकि उसमें विनिर्दिष्ट  
उपभोक्ता सहकारी समितियों और अन्य सहकारी संस्थाएं  
घटे मार्जिन पर बैंकिंग भ्रमिकरणों से कार्यकर पूर्जी के लिए  
अद्देन प्राप्त कर सकें।

2. उपभोक्ता सहकारी समितियों को बैंकिंग संस्थानों  
में 10 प्रतिशत के घटे हुए मार्जिन पर कार्यकर पूर्जी की मांग

की बढ़ती हुई आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, भारत  
सरकार ने केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति योजना को आठवीं  
पंचवर्षीय योजना प्रर्थात् 1-4-1990 से 31-3-1995 तक  
5 वर्ष की और अवधि के लिए जालाने का निर्णय किया  
है।

3. मब सहकारी संस्थाएं जो कार्य साधक के लिए  
विनीय संस्थाओं में इस योजना के अन्तर्गत अद्देन लेना  
चाहेंगे उनको एक प्रतिशत की प्रतिवर्ष की दर से गारंटी  
फीस देय होगी।

4. उपर्युक्त विनियोग के अनुसरण में, भारत सरकार,  
उपबंध-1 में दिए गए प्रत्याभूति विलेख प्रृष्ठ में, किसी भी  
शीर्ष/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रम  
का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित  
और कार्य कर रहे किसी भी बैंक/भारतीय स्टेट बैंक अधि-  
नियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय  
स्टेट बैंक (ममनुवंगी बैंक अधिनियम, 1959) में यथा

परिवाधित किसी समनुधानी बैंक के साथ उनके द्वारा निम्नलिखित को दिए गए प्रतिभूति अग्रिम धनों की बाबत, करार करने पर विचार करेगी, अर्थात् :—

- (1) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ
- (2) उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के सभी राज्य परिसंघ ।
- (3) सभी थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी सोसायटियां।
- (4) किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता वस्तुओं के कारबार में लगे हुए सभी राज्य स्तरीय सहकारी परिसंघ, परन्तु इस प्रत्याभूति के अधीन संरक्षण केवल उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए उनकी कामकाज पुंजी संबंधी अपेक्षाओं तक ही निर्बंधित रहेगा ।
- (5) किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के खुदरा कारबार में लगी हुई ऐसी सभी सहकारी संस्थाएं, जिनका विक्रय आवर्त कम से कम 20 लाख रुपये प्रति वर्ष है तथा सहकारिता की दृष्टि से अत्यविकसित राज्यों/असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड) में ऐसी वे संस्थाएं जिनका न्यूनतम वार्षिक विक्रय आवर्त 10 लाख रुपये है ।

5. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति, ऊपर पैरा 4(1) से 4(5) में उल्लिखित सभी सहकारी संस्थाओं को ऐसे माल को गिरवी या आडमान के बदले में, जिसके अन्तर्गत वही ऋण, प्रत्याभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सम्पत्ति भी है, प्रतिभूति लिखित पूर्व अनुमोदन से, 1-4-1995 से पूर्व वाली विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभूति उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत ही उपलब्ध होगी। बैंकों को ऐसे उधारों तथा अग्रिम धनों पर केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखना है। किसी सोसायटी को दिए गए किसी ऐसे उधार या अग्रिम धन की बाबत केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के अधीन देयता, निम्नलिखित में से जो भी कम है वहां तक सीमित होगी, अर्थात् :—

- (1) उस तारीख को, जिसको करार के निवधनों के अनुसार मांग की सूचना बैंक द्वारा जारी की गई है सहकारी सोसायटी के नाम बैंक की बहियों में वस्तुतः बकाया सब प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम धनों की रकम का 25 प्रतिशत; या
- (2) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ की दशा में 150 लाख रुपए (एक करोड़ पचास लाख रुपये), सभी राज्य स्तरीय परिसंघों को, जिनके अन्तर्गत पैरा 4(4) में उल्लिखित सहकारी संस्थाएं भी हैं दशा में 100 लाख रुपये (एक करोड़ रुपये) तथा अन्य सभी सहकारी संस्थाओं की, जिनके अन्तर्गत पैरा 4(4) में उल्लिखित संस्थाएं भी हैं,

चाहे उनके कारबार का व्यापार गृहानगरी में हो गा कहीं थार है, दशा में 60 लाख रुपये (साठ लाख रुपये) इनमें से जो भी कम हो ।

6. इस अधिसूचना के अनुसरण में प्रत्याभूति, सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन से, 1-4-1995 से पूर्व वाली विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभूति उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत उपलब्ध होगा। 1-4-1995 को या उसके पश्चात प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अग्रिम धन और 31 मार्च 1995 को विद्यमान किसी उधार या अग्रिम धन की बाबत बकाया रकम में कोई भी वृद्धि प्रत्याभूति के अन्तर्गत नहीं आएगी। इस प्रत्याभूति के कारण उत्पन्न हुए केन्द्रीय सरकार का दायित्व 31 मार्च, 1995 को कारबार के बंद होने के समय समाप्त हो जाएगा।

7. सोसायटी, भारत के राष्ट्रपति के साथ इसमें उपावद्ध प्रत्याभूति-विलेख को प्रथम अनुसूची में उपबंधित प्रृष्ठ में एक करार करके निम्नलिखित के लिए वचनवद्ध होगी, अर्थात् —

- (क) उधार, अग्रिम धन या नकद उधार मंजूर करते समय बैंक द्वारा अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को नियमित रूप से और शीघ्रता में संदर्भ करने के लिए;
- (ख) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसायटी का कारबार तत्परतापूर्वक करने के लिए;
- (ग) केन्द्रीय सरकार को उन सब धनराशियों का प्रतिसंदाय मांग पर बिना किसी आपत्ति के करने की प्रत्याभूति देने के लिए, जो बैंक द्वारा सोसायटी की ओर से बैंक को सदाय करने में चूक के कारण केन्द्रीय सरकार से बसूल की जाए;
- (घ) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पढ़ति को कार्यान्वयित करने, तदोपरान्त, स्टाक में हुई कमियों का तत्काल निर्धारण करने, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करने और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की बसूली करने के लिए;
- (इ) सोसाइटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाएं देने में कड़ी सावधानी बरतने और साथ ही उसकी व्यवस्थित तथा तत्काल बसूली के लिए उपाय करने के लिए;
- (च) प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलनपत्र का और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबंध रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करने और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए;
- (छ) सोसाइटी की सम्पत्तियों और आस्तियों, को उन बिल्लगमों तथा कुकियों से भिन्न बिल्लगमों और कुकियों से मुक्त रखने के लिए, जो बैंक के पक्ष में हो तथा जिनके बारे में सरकार ने बैंक को

प्रत्याभूति दी है अथवा जो ग़ज़य सरकारों के पथ में हैं; और

(ज) केन्द्रीय सरकार या इस निर्मित उसके द्वारा नाम विनिश्चित किए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सोसायटी के लेखांशों तथा उसके कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए ममी मुविधाएं प्रदान करने के लिए।

यह नामर धन राशि निकालन की तारीख से पूर्व निष्पादित किया जाएगा। बैंक कोई संदाय नब तक नहीं करेगा जब तक कि हस्ताक्षरित करार तथा प्रत्याभूति विनेश्व के द्वितीय अनुसूची में उपब्रहित प्रक्षय में सम्पन्न पत्र नहीं दें दिए जाते हैं।

8. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति, बैंक द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिम धनों पर ब्याज के लिए लाग नहीं होती है।

9. प्रत्येक बैंक ऐसे सभी वक्तव्य-पत्रों या वसूलन की गई प्रतिभूतियों को, जो बैंकों को उनके द्वारा सोसायटी को दिए गए ऐसे उधारों के बारे में उपलब्ध हों, केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिम धनों की वावन बैंकों को देय सम्पूर्ण बकाया को उनके द्वारा वसूली के बाद की तब तक प्रतिधारित रखेगा जब कि प्रत्याभूति दाता के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ण रकम की वसूली न हो जाए।

10. बैंक प्रत्याभूति विनेश्व की किसी दूसरी अनुसूची में दिया गया इस आशय का। एक सम्पत्ति पत्र सोसायटी में अभिप्राप्त करेगा और केन्द्रीय सरकार को देगा कि सोसायटी निम्नलिखित रूप में करार करती है कि—

(क) वह प्रत्याभूति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंक की संदत्त की गई किसी रकम पर ब्याज उसी दर में जिस दर से सोसायटी का दिए गए उधार या अग्रिम धन पर ब्याज बैंक द्वारा प्रभारित किया गया है या किया जाए, नब तक देती रहेगी जब तक उक्त रकम केन्द्रीय सरकार को संदत्त या उसके पक्ष में समायोजित नहीं कर दी जानी;

(ख) वह उस तारीख के पश्चात जिसको प्रत्याभूति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने किसी रकम की प्रतिपूर्ति बैंक को की है, किन्तु प्रत्याभूति के अन्तर्गत अनेक बैंक के दावे की पूरी-पूरी मुष्टि हो जाने के पश्चात् और उस समय तक जब तक कि उन रकमों की जो उधार सुदूर सोसायटी द्वारा मंजूर या जारी पत्रों की गई है जो उस पर अतः उधार प्रभारी भाई दोसायटी द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं कर दी जाती, उधार या अग्रिम

धन लेखे सोसायटी द्वारा की गई या उसमें वसूल केवल की गई सब रकमों को प्रतिभूति (केन्द्रीय सरकार) के खाते में जमा होने देगी या जमा करने के लिए बैंक को अनुज्ञा देगी।

(ग) सब ऐसे उधारों नवा अग्रिम धनों की वावन बैंक के पक्ष में भी प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार बैंक के पास होंगे और वह उनका प्रयोग तब तक करता रहेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे सब दावों की पूष्टि नहीं हो जाती; और

(घ) बैंक ऐसी प्रतिभूतियों के अधीन अपने अधिकारों और दावों का अंतरण केन्द्रीय सरकार को उस दशा में करेगा जब पश्चात्कार्यत द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए।

11. बैंक का यह समाधान हो जाने की दशा में कि सोसायटी प्रत्याभूति के अधीन दिए गए अग्रिम धन के प्रति बैंक की नियमित विप्रेषण करने में असफल रही है या किसी प्रत्याभूति को चालू रखने के लिए उसकी समाप्ति के पूर्व लिखित रूप में प्रतिभूति का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने में असफल रहती है तो बैंक घटाए गए माजिन पर सोसायटी द्वारा और धन प्राप्त करने की अनुज्ञा नहीं देगा तथा सोसायटी द्वारा सभी आगे के विप्रेषणों को प्रत्याभूत कृण के खाते में तब तक जमा करता रहेगा जब तक कि वे पूर्ण रूप से प्रतिसंदत्त नहीं हो जाता।

12. बैंक द्वारा किसी विशिष्ट सोसायटी की वावन केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति का आश्रय एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा। प्रत्याभूति का आश्रय 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व किसी भी समय दिया जा सकेगा। बैंक पहले सोसायटी के नाम इस प्रभाव की मांग सूचना जारी करेगा कि वह उस रकम को, जो बैंक द्वारा दिए गए हैं और प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों और अग्रिम धनों के लेखे बैंक को देय हों, उस तारीख से 30 दिन के भीतर संपत्ति करे जिसको ऐसे प्रतिसंबाध मांगने का सूचना बैंक द्वारा नामील की गई है। ऐसी मांग की सूचना की एक प्रतिलिपि प्रतिभूति को भी साथ साथ पृष्ठांकित की जानी चाहिए। यदि सोसायटी उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति तक रकमों का संबाध नहीं करती है तो बैंक केन्द्रीय सरकार के नाम मांग की सूचना जारी करेगा। केन्द्रीय सरकार बैंक को प्रत्याभूति के अधीन संदेश रकम की प्रतिपूर्ति उस तारीख के 90 दिन के भीतर करेगी जिसकी उसे प्रत्याभूति की आश्रय देने और संबाध का दावा करने की बैंक की सूचना प्राप्त हों।

13. इस अधिसूचना के अनुसरण में प्रत्याभूति चाहते वाले बैंक, किसी उधार या अग्रिम धन की वावन सरकार की प्रत्याभूति का आश्रय लिए जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार के नाम इन रकमों को जमा करने के लिए वचनबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम धनों की पूरी वसूली बैंक द्वारा गोमायटी से लिए जाने के पश्चात सोसायटी से वसूल की जाए। बैंक के लिए यह

बाध्यकर होना कि वह प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा रकम की प्रतिपूर्ति कर दिए जाने के पश्चात उपरोक्त रीति से कार्यवाही करे।

14. उपरोक्त खण्डों में निर्दिष्ट बैंक की बाध्यताएं, उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि वह रकम जिसको प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई है केन्द्रीय सरकार को संदर्भ नहीं कर दी जाती है या केन्द्रीय सरकार के नाम जमा नहीं कर दी जाती है या जब तक केन्द्रीय सरकार उक्त रकम का समायोजन अपने द्वारा बैंक या सोसायटी को मद्देय किसी अन्य रकम से करते या उस रकम को वसूली का अधित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाती।

15. संबद्ध राज्य की सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार बैंक और प्रशासनिक रूप में सोसायटी के कार्यकरण का नियमित पर्यवेक्षण करने तथा सोसायटी के कार्यों और गतिविधियों में किन्हीं प्रतिकूल लक्षणों के पाए जाने की दशा में या यदि सोसायटी द्वारा अनियमित विप्रेषणों या सोसायटी के कार्यकरण में किन्हीं अन्य अवांछनीय विस्तीर्ण बातों के संबंध में बैंक द्वारा कोई रिपोर्ट की जाने की दशा में समुचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए भी सक्षम प्राधिकारी होगा। यह स्पष्टतः समझ लिया जाए कि यह प्रत्याभूति के बल तभी दी जाएगी जब संबद्ध राज्य की सहकारी सोसायटियों के रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित प्रस्ताव की सिफारिश की जाएगी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा की गई सिफारिश को ऐसे रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया यह आश्वासन समझा जाएगा, कि सोसायटी के कार्यों और गतिविधियों के संबंध में बैंक और/या भारत सरकार से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, समुचित उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

16. भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में, जो उपभोक्ता सहकारी समितियां, नई दिल्ली से संबंधित करता है, निवेशक उपसचिव की पक्षित या उससे उच्चतर पंक्ति का कोई अधिकारी हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्भव रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिसूचना के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के संबंध में बैंकों के साथ प्रत्याभूति का विहित करार करने के लिए प्राधिकारी होगा। अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी बैंकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे ऊपर उपदण्डित मंत्रालय में प्रत्याभूति तथा प्रवर्तन के भारतीय अधिकारी से संपर्क स्थापित करें।

डा. प्रदीप मोंगा, निवेशक

#### प्रत्याभूति विलेख

एक पक्षकार के रूप में भारत के गढ़पति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात प्रतिभूति कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में जो बैंककारी कम्पनी (उपरोक्त का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970

के अधीन गठित तथा संचालित बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित किया गया निगम है।

(बैंक का नाम) जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुपगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किया गया निगम है। अधीन रजिस्ट्रीकून महकारी सोसायटी है, और जिसका कार्यालय में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "बैंक" कहा गया है) के बीच 19 के/की दिन किया गया यह प्रत्याभूति-विलेख निम्नलिखित का साथी है :

बैंक द्वारा ..... को (जिसे इसमें इसके पश्चात "सोसायटी" कहा गया है) पश्चात कथित के निवेदन पर, उन मार्जिनों को शिथिल करके जो इस प्रत्याभूति की अनुपस्थिति में बैंक सामान्य रूप से अनुसरण करता, प्रतिभूति बैंक को इसमें इसके पश्चात उपबंधित परिमाण तक उधारों और अग्रिम धनों को सोसायटी द्वारा बैंक को प्रतिसंदाय, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर प्रत्याभूति करता है, जो इसमें इसके पश्चात उल्लिखित है :

1. प्रतिभूति की प्रत्याभूति, बैंक द्वारा प्रतिभूति के लिखित पूर्व अनुमोदन से सोसायटी को विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व दिए गए किसी ऐसे प्रतिभूति उधार या अग्रिम धन की बाबत ही उपलब्ध होगी जो माल की गिरवी या आडमान के बदले में, जिसके अन्तर्गत वही छूट, प्रतिभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सम्पत्ति भी है, दिया गया हो। बैंक ऐसे उधारों और अग्रिम धनों के लिए केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखने के लिए सहमत है।

2. उक्त सोसायटी जो उपरोक्त रूप में दिए गए उधार या अग्रिम धन की बाबत प्रतिभूति का वायित्व, किसी भी समय, निम्नलिखित में से जो भी रकम सबसे कम हो उसमें प्रधिक नहीं होगा :—

(1) उस तारीख को जिसको प्रतिभूति के नाम मांग की सूचना इसके छंड (3) के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा जारी की जाती है, सोसायटी के नाम बैंक द्वारा जारी की जाती है, सोसायटी के नाम बैंक की अधियों में वस्तुतः बकाया प्रत्याभूति किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों की रकम का पच्चीस प्रतिशत; या

(2) ..... लाख रुपये।

3. बैंक 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व किसी भी समय प्रतिभूति को प्रत्याभूति का आसरा इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट नीति से ले भकेगा, अर्थात् :—

(1) बैंक पहले मोराइटी के नाम इस मांग की सूचना जारी करेगा कि वह उन रकमों को, जो उसे बैंक द्वारा दिए गए और प्रतिभूति प्रत्याभूत किए गए

उधारों और अग्रिम धनों लेखे अपने को देय हों, उम तारीख से तीस दिन के भीतर संदत करे जिसको ऐसा प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा उधारों की गई है। उस मांग नोटिस की एक प्रतिलिपि प्रतिभू को भी साथ-साथ पुष्टांकित की जानी चाहिए।

(2) यदि सोसाइटी, यथापूर्वोक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर, बैंक द्वारा उसे दिए गए और प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों का संदाय नहीं करती है, तो बैंक प्रतिभू के नाम मांग की सूचना जारी करेगा।

(3) बैंक प्रतिभू की प्रत्याभूति का आमरा लेने समय, प्रतिभू को निम्नलिखित विवरण देगा:—

(1) उन मालों का व्यौरा, जिन पर ऐसा उधार या अग्रिम धन दिया गया है जिसकी बाबत प्रत्याभूति का आसरा लिया गया है;

(2) उक्त मालों की बाजार मूल्य; और

(3) निम्नलिखित तारीखों को सोसाइटी के नाम बकाया रकमें:—

(क) वह तारीख जिसको प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा सोसाइटी के नाम जारी की गई थी—तथा

(ख) प्रतिसंदाय मांगने की सूचना की तारीख से तीस दिन को समाप्ति की तारीख, और

(4) प्रतिभू बैंक को देय रकम की इस प्रत्याभूति में उपबंधित परिमाण तक प्रतिपूर्ति उस तारीख से 90 दिन के भीतर करेगा जिसको प्रत्याभूति का आसरा लेने और संदाय का दावा करने की बैंक की सूचना प्रतिभू ने प्राप्त की हो।

4. इसमें अंतिम प्रत्याभूति इस बात के होते हुए भी प्रतिभू के बिल्डु प्रश्न की जा सकेगी कि कोई प्रतिभूतियां जो बैंक ने सोसाइटी से अर्भप्राप्त की हो, बकाया हों, या बसूल न की गई हों।

5. प्रत्याभूति विलेख की प्रथम अनुसूची में उपाबद्ध प्रणय में सोसाइटी भारत के राष्ट्रपति के साथ एक करार करेगी और इसके लिए वचनबद्ध करती है कि वह:—

(क) बैंक द्वारा उधार, अग्रिम धन या नकद उधार में और करते समय अधिकारित गतों के अनुसार बैंक के देयों को निर्यात रूप में और शीघ्रता में संदत करेगी,

(ख) लाभ फसाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारधार तत्परतापूर्वक करेगी,

(ग) केन्द्रीय सरकार को उन सब धनराशियों का प्रतिसंदाय, मांग पर बिना पूर्वापिन के करने को भी प्रत्याभूति देगी जो बैंक द्वारा सोसाइटी की ओर से बैंक को संदाय करने में व्यक्तिका के कलम्बन्य केन्द्रीय सरकार से बसूल की जाए,

(घ) स्टार्कों के नियमित सत्यापन की पढ़ति को कार्यान्वित करेगी, तदोपरांत कर्मियों का ताकान निर्धारण करेगी, उसके लिए जिम्मेदारी नियम करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों में उनके मूल्य को बसूली करेगी,

(ङ) सोसाइटी, सहायताओं और व्यक्तियों को उधार देने की सूचियाओं का विस्तार करने में बड़ी सावधानी बर्खेगी और साथ साथ उनकी ध्यानित तथा तत्कान बसूली के लिए उपाय करेगी;

(च) प्रत्येक तिमाही को अंतिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हार्नि और तुलनपत्र का तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रवेध रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति प्रतिभू की भेजेगी,

(छ) सोसाइटी की सम्पत्तियों और आर्मिन्यों को उन विलंगमों तथा कुकियों से मुक्त रखेगी—जो उनके प्रलापा है, जो बैंक के पक्ष में हैं तथा जिसके बारे में सरकार ने बैंक को प्रत्याभूति दी है अथवा जो राज्य सरकारों के पक्ष में हैं; और

(ज) प्रतिभू या इस निर्मित उनके द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने लेखाओं तथा अपने कार्यकरण को परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी।

बैंक सोसाइटी को तब तक कोई संदाय नहीं करेगा जब तक कि प्रत्याभूति विलेख को प्रथम अनुसूची के प्रलैप में करार तथा द्वितीय अनुसूची में वे सम्पत्ति पत्र पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से निर्धारित करके उसे नहीं दे दिए जाते।

6. बैंक उस प्रत्याभूति के प्रति कलम्बन्य और उसकी प्रतिभू से उपलब्ध है, निम्नलिखित बातों के लिए सहमत होगा:—

(क) प्रतिभू को ऐसा कोई रकम संबत्त करना या उसके बाते में जमा करना जो प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत रकम की प्रतिपूर्ति कर दिए जाने को तारीख के पश्चात, प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम धनों को पूरी बसूली उसके द्वारा कर लिए जाने के पश्चात सोसाइटी से बसूल की जाएगी,

(ख) ऐसे सब वचन पत्रों या बसूल न की गई प्रतिभूतियों की, जो बैंक द्वारा सोसाइटी दो दिए गए उधारों के बारे में उसे उपलब्ध हों, बैंक को देय

समूर्ण ब्रक्यार्या को उसके द्वारा वसूली के पश्चात भी नव तक प्रतिवारित रखना जब तक प्रतिम द्वारा प्रतिपूरित रकम की वसूली न दो जाएँ।

(ग) इसकी द्वितीय अनुसूची में उपर्युक्त प्रथम में एक सम्पति पत्र सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिम को देना;

(घ) यदि प्रतिम द्वारा अपेक्षा की जाएँ जो अपने को देव ब्राह्मण को पूरी वसूली बैंक द्वारा कर दिए जाने के पश्चात सब ऐसे बचत पत्रों या प्रतिभूतियों को प्रतिम तथा/या उसके नाम-निर्देशिनी को अंतर्गत करना किन्तु यह नव जब कि प्रतिम को उसके द्वारा दी गई रकम की प्रतिपूर्ति न की गई हों; और

(ङ) इसके 'उत्तराब्द प्रत्यासुनिविलेख' की प्रथम अनुसूची में उपर्युक्त प्रथम में एक करार सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिम को देना, जैसा कि उसके खंड 5 में उपर्युक्त किया गया है।

7. प्रतिम को प्रत्याभूति सोसाइटी को मंजूर किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों और ज्यात्र के बारे में लागू नहीं होंगी।

8. खंड (6) के उपर्युक्तों के अनुसरण में बैंक को बाध्यताएँ उस समय तक जारी रहेंगी जब तक वह रकम जिसकी प्रतिम द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है प्रतिम को बुका नहीं दी जाती या उसके नाम जमा नहीं करकी जाती या जब तक प्रतिम अपने द्वारा बैंक या सोसाइटी को संदेत की जाने वाली अन्य शोध्य रकम के साथ उक्त रकम का समायोजन न करने या उस रकम की वसूली का अधित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

9. इस सोसाइटी की वाजत प्रतिम को प्रत्याभूति का आसरा बैंक द्वारा एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा और यदि प्रतिम को प्रत्याभूति का आसरा निया गया है या उसका आसरा लेने के पश्चात कोई उधार या अग्रिमधन उस सोसाइटी को दिया जाना है जिसकी ओर से कोई रकम बैंक को प्रतिम द्वारा की गई है, तो कोई भी ऐसा उधार या अग्रिम धन बैंक को अपनी जोखिम पर होगा। और ऐसे अर्तारक्त उधार या अग्रिम धन के लिए प्रतिम का कोई दायित्व नहीं होगा।

10. 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अग्रिम धन और 31 मार्च, 1995 को विद्यमान किसी भी उधार या अग्रिम धन को पश्चात बायाया। याम गे कोई भी बद्दि प्रतिग्रहण द्वारा प्रत्याभूत नहीं हो पायेगा। याम गे के दिन, 31 मार्च, 1995 को कारबाह द्वंद होने के समय भमात हो जाएगा।

11. प्रतिम, ऐसे उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत जिनके संबंध में यह प्रत्याभूति बैंक को उपलब्ध है, ऐसी जानकारी और विवरणियाँ बैंक से अभिप्राप्त करने के लिए हकदार होगा। और बैंक ऐसी जानकारी और विवरणियाँ ऐसे अंतरालों पर या ऐसी रीति में देगा जैसी प्रतिम द्वारा विनिर्दिष्ट या अपेक्षित की जाएँ।

12. यदि इस प्रकार से उद्भूत या उसके संबंध में या इसके अर्थ या निर्वचन के बारे में अथवा इस कागर की बाबत अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई मानेद या विवाद इसके पक्षकारों के बीच हो तो वह तत्प्रथम भारत सरकार के ऊपर विधि समाजदार (माध्यस्थम) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम के लिए निर्वाचित किया जाएगा और उस अधिकारी का विनियोग अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर आवादकर होगा। यह कोई अपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है, उसे उन मामलों में जिनसे यह प्रत्याभूति संबंधित है, कारबाही करनी पड़ी थी या सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के श्रनुकम में वह उन सब बातों पर या उनमें से किसी पर, जिनके बारे में विवाद या मतभेद है अपने विवार प्रकट कर लूका है। मध्यस्थम अधिनियम, 1940 के उपर्युक्त या उसके कोई कानूनी उपात्तरण या पुनः अधिनियमित ऐसे माध्यस्थम को लागू होंगे। माध्यस्थम कार्यविधियाँ उस स्थान पर को जाएगी जिसे माध्यस्थ विनियिचत करे। मध्यस्थ को यह हक होगा कि वह पंचाट करने का समय पक्षकारों को समानि से समय समय पर बढ़ा सके।

13. इस प्रत्याभूति विकेत्ता पर देव स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा।

14. इसके सक्षम्बल्य प्रतिम और बैंक ने यह विवेच ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को सम्बन्ध रूप से निष्पादित कराया है।

निदेशक (प्रत्याभूति) तथा प्रत्याभूत भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से परिसर में कार्यकारी भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में जो उपसोक्ता सहकारी समितियों में संबद्धतार करता है।

निम्नलिखित की उपस्थिति में साक्षी

(1)

(2)

प्रथम अनुसूची

कागर

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, (जिन्हें इसमें द्वारा कोष्ठात्र "कर्तव्य सरकार" कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत, जब वह दिन में अग्रिम धन या उपर्युक्त नहीं हो, उसके पद उत्तराधीन और समनुरक्षित भी समझे जाएंगे।

प्रीति लूटे पश्चात् के रथ में —  
श्रीयीन र्जिस्ट्रीस्ट — मृत्युगी  
भासाइटी है और जिसका र्जिस्ट्रीकृत/केन्द्रीय/मुख्य कार्यालय

में है (जिसे इनमें इसके पश्चात् “सोसाइटी” कहा गया है  
जिस पद के अन्तर्गत, नव तक संदर्भ से अपवाजित या उसके  
विकल्प न हो, उसके नियादन, प्रशासन, प्रतिनिधि और अनु-  
ज्ञान समनुदेशियों और उस्तराधिकारी भी सनने जाएंगे) के  
बीच आज 19 के/की दिन किया गया यह करार  
प्रिमानियित का साक्षी है:—

बैंक के द्वारा, सोसाइटी को  
उधार अप्रिम धन, नकद उधार सीमाएं और मन्त्र बैंककारी  
मुविधाएं और गोकर्ण देने के प्रतिकल स्वरूप, अन्य बातों के  
साथ नाथ बैंक द्वारा सोसाइटी को दिए गए उधार और अप्रिम  
धन के एक भाग के प्रति संशय को केन्द्रीय सरकार के द्वारा  
प्रत्याभूति देने पर, सोसाइटी केन्द्रीय सरकार से एतद्वारा  
वचनबद्ध करती है, कि वह:—

- (1) बैंक द्वारा, उधार, अप्रिम धन या नकद उधार  
मंजूर करने समय अधिकारित शर्तों के अनुसार  
बैंक के शोध्यों को नियमित रूप से और शीघ्रता  
से संदर्भ करेगी;
- (2) नाम कमाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारोबार  
नव्यनापूर्वक करेगी;
- (3) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति को कार्या-  
न्वित करेगी, तदोपरान्त कमियों का तत्काल निर्धा-  
रण करेगी, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करेगी  
और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली  
करेगी।
- (4) सोसाइटीयों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार  
देने की सुविधाओं का विस्तार करने में बड़ी  
साक्षाती बरतेगी और साथ ही उनकी व्यवस्थित  
तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करेगी;
- (5) प्रत्येक निमाही की अंतिम तारीख को तिमाही  
व्यापार और नाभ तथा हानि और तुकन-पत्र  
तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी  
के कार्यकरण की तिमाही प्रबंध रिपोर्ट का तैयार  
किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही  
में उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को और  
राज्य सरकार को भी भेजेगी।
- (6) सोसाइटी को अधिनियमों और आदिनियमों को विनाशम  
तथा कुर्कियों से मुक्त रखेगी — जो उनके ग्रान्त  
हैं, जो बैंक के पात्र में हैं तथा जिनके बारे में  
सरकार ने बैंक को प्रत्याभूति दी है अथवा जो  
जो राज्य सरकार के पक्ष में है, और

(7) केन्द्रीय गवाहार सा इस प्रिमिन उपर्युक्त ग्रान्त  
निर्देशित किए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को  
अपने लेखा तथा अपने कार्यकरण की परीक्षा करने  
के लिए सभी गुप्तियाँ प्रदान करेगी।

2. सोसाइटी, केन्द्रीय सरकार की उन सब धनराशियों  
को प्रतिसंदाय मांग पर विना पूर्व आपत्ति के, कर्त्ता की  
प्रत्याभूति करती है और बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार पर सोसाइटी  
की ओर से लिए गए व्यतिक्रम के फलस्वरूप वसूल की जाए।

3. उपरोक्त खण्ड 2 के सिवाय, इस करार से उद्भूत  
होने वाले या इससे किसी प्रकार से संबद्ध या संबंधित सभी  
विवाद और मतभेद भारत सरकार के ऊपर विधिसन्निवारण  
(माध्यस्थम) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के एक मात्र  
माध्यस्थम के लिए निर्देशित किए जाएंगे। यह कोई आपत्ति  
नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है या कि उसने विवाद  
या मतभेद के सभी या किसी सामने पर अपने विचार प्रकट  
किए थे। भारतीय माध्यस्थम अधिनियम के उपर्युक्त ऐसे  
माध्यस्थमों को लागू होंगे। माध्यस्थ का पंचायत अंतिम होगा  
और दोनों पक्षकारों पर अबद्धकर होगा।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और  
उसकी ओर से —  
(नाम और पदाभिमान) द्वारा हस्ता-  
भरित सोसाइटी के प्रविधुत प्रति-  
निधि (प्रतिनिधियों) द्वारा हस्ताक्षरित  
(नाम और पदाभिमान)

साक्षी—

(1)

(2)

द्वितीय अनुसूची

नामानि—पत्र

मेवा में,

1. —————— बैंक

2. भारत के राष्ट्रपति।

द्वारा (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् “बैंक” कहा गया है)  
को यिए गए उदारों तथा अप्रिम धनों के एक भाग में प्रति  
संदाय को प्रत्याभूत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें  
इसमें इसके पात्रान् “राष्ट्रपति” कहा गया है) के सहमत हो  
जाने के फलस्वरूप हम यह करते हैं कि कोई भी वचन  
पत्र और माल की तिरवी या आडवान के लिए में कोई भी  
प्रतिमूलि, जिसके अन्तर्गत वही, अण प्रतिभूतियों, विनिधान  
और ग्रन्त जंगम भवति नहीं है जो ऐसे उदारों और अप्रिम  
धनों के संबंध में आंत बैंक को दी है और हमारे द्वारा दी  
जाए, इस बात के होने द्वारा भी अनित्य में रहेगी तथा बैंक

द्वारा प्रतिपादित की जा रही कि राष्ट्रपति द्वारा वैसों की दी गई प्रत्याभूति के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने हमारे खाते में की किसी कमी को पूरा कर दिया है, हम यह और करार करने हैं कि:—

(क) हम राष्ट्रपति को प्रत्याभूति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा बैंक को दी गई किसी रकम पर व्याज, उसी दर से जिस दर से हम को दिए गए उधार या अधिग्राम धन पर व्याज बैंक द्वारा प्रभारित किया गया था किया जाए, तब तक दें रहेंगे जब तक उक्त रकम राष्ट्रपति को संवत्त या उनके पक्ष से समाप्तिजन नहीं कर दी जाती;

(ख) उस तारीख के पश्चात जिसकी अपनी प्रत्याभूति के अनुसरण में राष्ट्रपति ने किसी रकम की बावत बैंक की प्रतिभूति की है किन्तु राष्ट्रपति को प्रत्याभूतियों के अन्तर्गत आने वाले उधारों तथा अधिग्राम धनों की बावत बैंक के दावे को पूरी पूरी सुषिट हो जाने के पश्चात और उस समय तक जब तक उन रकमों की, जिनकी राष्ट्रपति द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है, उन पर व्याज तथा प्रभारों सहित, हमारे द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं कर दी गई था हमें बगूल की गई सब रकमों को जमा करने के लिए बैंक की अनुज्ञा देंगे।

(ग) ऐसे सब उधारों तथा अधिग्राम धनों की बावत बैंकों के पक्ष में की गई प्रतिभूतियों के बारे में सभी अधिकार बैंक के पास रहेंगे और वह उनका प्रयोग तब तक करना रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति के ऐसे मधी दावों की, जो खंड (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं, तुष्टि नहीं हो जाती, और

(घ) ऐसी प्रतिभूतियों के अधीन अपने अधिकारों तथा दावों या बैंक उस दशा में राष्ट्रपति को अंतरण करेगा, जबकि उनके द्वारा या उनकी ओर में ऐसी अपेक्षा की जाए।

सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित (नाम और पद-भिन्न)

साक्षी—

( 1 )

( 2 )

### अनुबंध—II

अधिभूता संख्या औ— 17011/2/89— सी. एफ. एम. दिनांक 1-11-1990 के द्वारा परिचालित केन्द्रीय मरकार की प्रत्याभूति योजना के तहत राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों में घटी वर्षों पर कार्यकर पूँजी शृण प्राप्त करने के लिए

केन्द्रीय नरसार प्रत्याभूति की पूँजी देते प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया :

जो संस्था केन्द्रीय मरकार की प्रत्याभूति (गारंटी) चाहती है, उसे अपना प्रस्ताव निम्नलिखित भूचना और कागजात के साथ प्रस्तुत करना होगा:—

( 1 ) निर्धारित फार्म (परिशिष्ट—I) में संस्था का बौरा दिया जाए तथा साथ ही यदि उसकी विक्षी और लाभकारिता में किसी वर्ष विशेष में कमी आई है तो उसके कारण दिए जाएं।

( 2 ) निदेशक मंडल का संकल्प (परिशिष्ट—II), जिसमें केन्द्रीय सरकार की गारंटी के तहत किसी बैंक विषेष से कार्यकारी शृण प्राप्त करने के लिए मंस्था के निर्णय का उल्लेख हो, जो शावेदत पत्र की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना न हो, भेजा जाए और साथ ही उसमें आवश्यक घोषित कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति/व्यक्तियों को भी प्राधिकृत किया गया हो।

( 3 ) अधिसूचना की प्रथम अनुसूची में दिया गया करार, प्रपत्र, जिस पर प्राधिकृत व्यक्तियों और पूरे पतों सहित दो साक्षियों के विधिवत हस्ताक्षर हों, भेजा जाए।

( 4 ) अधिसूचना की दूसरी अनुसूची में दिया गया सम्मतिपत्र, जिस पर प्राधिकृत व्यक्तियों और पूरे पतों सहित दो साक्षियों के विधिवत हस्ताक्षर हों, भेजा जाए।

( 5 ) पिछले चार सहकारी वर्षों के लिए लेखाओं का लेखा परीक्षित कच्चा विवरण अर्थात् व्यापार और लाभ तथा हानि लेखा व सुलनपत्र भेजा जाए। इनमें से कम में कम दो वर्षों के लेखा विवरण लेखा परीक्षित हो तथा साथ साथ बाद के छमाही/तिमाही के कच्चे लेखा हों। लेखा परीक्षा पूरी होने के संबंध में प्रमाणपत्र भी शामिल किया जाए।

( 6 ) यदि किसी मंस्था को पिछले चार वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में, जिसमें चालू वर्ष भी शामिल है, हानि हुई हो तो हानि होने के विस्तृत कारण दिए जाएं और साथ ही पुनः लाभकारिता प्राप्त करने के लिए उक्त सोसाइटी द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों का भी उक्त टिप्पण में उल्लेख किया जाए।

( 7 ) सोसाइटी की उपविधियों की एक प्रति।

( 8 ) सोसाइटी की अधिकतम शृण लेने की सीमा का प्रमाण पत्र।

(9) परिशिष्ट-III के अनुसार एक विवरण भेजा जा जिसमें अंतिम सहकारी बैंक के अन्त में स्वामित्वाधीन निधि के प्रयोग्य भाग का उल्लेख किया जाए।

2. ग्रामीण भूमि में गारंटी अधेक्षित है उसमें कम से कम तीन माह पूर्व उपर्युक्त आधार पर प्रस्ताव त्राव प्रतियों में नैयार किया जाए और एक प्रति वित्तदायी बैंक को नकद सावधान की मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाए। दूसरी प्रति सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक को, भारत सरकार को अपनी सिफारिशें भेजने के लिए प्रस्तुत की जाए और एक अन्य प्रति भारत सरकार को अग्रिम प्रति के रूप में भेजी जाए।

3. एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारंटी शुल्क भुगतान और लेखा अविकारी नागरिक पूति विभाग के नाम से बनवाए गए दिनों में देव डिमार्ड इंस्टट के जरिए आवेदन के साथ भेजा जाए।

4. आवेदन प्राप्त होने पर, प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बैंक के मामले को परिशिष्ट-IV में दिए गए प्रपत्र में भारत सरकार को सिफारिश के साथ भेजेगा। मामले की सिफारिश करते समय इस योजना के पैरा 10 की ओर बैंक का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाना है।

5. दूसरी अग्रिम प्रति प्राप्त होने पर सहकारी समितियों के पंजीयक परिशिष्ट-V पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार सूचना देते हुए अपनी सिफारिश के साथ मामला भारत सरकार को भेजेंगे। इस संबंध में उनमें ध्यान हम योजना के पैरा 14 की ओर आकर्षित किया जाता है।

6. वित्तदायी बैंक और सहकारी समितियों के पंजीयक की सिफारिशों उम तारीख से कम से कम एक माह पूर्व इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए, जिस तारीख में केन्द्रीय सरकार की गारंटी अधेक्षित है।

7. अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं भिया जाएगा।

#### परिशिष्ट-1

केन्द्रीय सरकार प्रथाभूति योजना के अन्तर्गत वित्तदायी बैंक से कार्यकारी पूँजी ऋण के लिए आवेदन करने वाले सहकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्यौरे (नवीनतम आंकड़ों पर आधारित)

1. सोसाइटी का नाम और पूरा पता :

2. गृह करने की तारीख सहित पंजीकरण की तारीख :

3. (क)

सदस्यों की संख्या

अंश पूँजी की राशि  
(लाख रु. में)

(1) व्यक्ति

(2) सोसाइटी/संस्थान

(3) सरकार

(4) कुल :

(ख) निदेशक मंडल का स्वरूप :

(1) निर्वाचित सदस्य

(2) नामित सदस्य

(3) कुल :

4. उधार लेने की शक्तियाँ

(क) बैंक में ऋण लेने की शक्तियों और सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा स्वीकृत कुल ऋण सीमा के बारे में सोसायटी के उप-नियमों/नियमों की संख्या का उल्लेख करें।

(ख) सोसायटी के प्रबंधकों द्वारा एक निश्चित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें सोसायटी की ऋण लेने की सीमा का उल्लेख किया गया हो।

5. केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति योजना के अन्तर्गत बैंक से ऋण और अधिक प्राप्त करने और इस संबंध में सोसायटी की तरफ से कागजात पर हस्ताक्षर भी करने के बासे सोसायटी के पदाधिकारी को प्राधिकृत करने हेतु एक संकल्प (प्रपत्र परिशिष्ट-II में) निदेशक मंडल/प्रबंध समिति द्वारा पारित किया जाए और उसकी प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जाए। (व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करें।)

6. नकद ऋण सीमा का अधिकत्य जिसके लिए आवेदन किया गया है, उसके साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचना भी दी जाए :

क.सं. सोसायटी द्वारा व्यापार की गई वस्तुएं/वस्तु-मूल

अनुमानित  
वार्षिक बिक्री  
(लाख रु. में)

रहितिया बारंबारित  
(वार्षिक बिक्री ÷ १)  
(आरंभिक स्टाक +  
अंतिम स्टाक)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

7. वांछित ऋण मुद्रिता का व्यौरा :

(क) नकद ऋण सीमा का आधार :

- (1) माल की गिरवी :
- (2) माल की बंधक :

(ख) अवधि जिसके लिए अधिक प्राप्ति की मांग की गई है। मांगे गए अधिक प्राप्ति की अवधि ।

8. कुल स्वामित्वाधीन निधि और स्वामित्वाधीन निधि का विनियोग्य अंश

(परिशिष्ट-III पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार)

9. ग्रामीणों की सं. ग्रामीण क्षेत्रों में

गंदी बस्ती और कमजोर वर्गों वाले क्षेत्रों में

समाज के अन्य वर्गों में

- (1) बहुविभागी भंडार
- (2) केवल उचित वर दुकानें
- (3) अन्य
- (4) कुल

10. विगत तीन महकारी वर्षों के दौरान बिक्री :

(लाख रु. में)

वर्ष

नियंत्रित वस्तुएं

गैर-नियंत्रित वस्तुएं

प्रावश्यक मद्दें

कुल

(1)

(2)

(3)

## 11. पिछले सहकारी वर्ष के अंत में अहूणों का विवरण :

अधिकरण	प्रयोजन	मंजूर की गई	वर्ष के दौरान निकाला	वर्ष के अंत में बकाया अहूण
		कुल राशि	गया अधिकतम अहूण	
(1) सरकार				
	(क) विशिष्ट परियोजना हेतु			
	(ख) कार्यकारी पूंजी हेतु			
(2) वित्तदायी बैंकों से				
(3) अन्य स्रोतों से				
	(कृपया उल्लेख करें)			
(4) कुल				

12. अंतिम दो लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और अंतिम सहकारिता वर्ष समाप्त होने तक बाब के वर्षों के प्रोफार्मा तुलन-पत्र लेखा परीक्षित लेखाओं, व्यापार, लाभ और हानि लेखाओं और तुलनपत्रों की एक प्रति संलग्न की जानी है। उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसने लेखाओं की लेखा परीक्षा की है।

13. पंजीयक द्वारा प्रदत्त लेखा परीक्षा का वर्ग

14. यदि भंडार इस समय घाटे में चल रहा है तो उसके क्या कारण हैं तथा सोसायटी के संचालन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार लाने के लिए कार्य योजना सहित उत्तर गण उपचारात्मक कदमों का व्यूहा वें एक अलग टिप्पण में उल्लेख करने हुए इस प्रोफार्मा के साथ मंलग्न करें।

15. मंस्थान द्वारा प्राप्त अब तक उपयोग की गई गारंटी मुश्किल/पुनर्वास सहायता का व्यूहा:

16. वित्तदायी बैंक की अहूणों/किसितों का भुगतान न कर पाने के कारण, यदि कोई हो :

17. 1 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क चुकाने वाले डिमाण्ड इफट का व्यूहा :

सोसायटी के अध्यक्ष/  
महाप्रबंधक/सचिव के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-II

निवेशक मंडल की ..... को हुई बैठक की कार्यवाही से उद्धरण।

कार्यसूची

केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के तहत बैंक से ..... रु. क नकद अहूण/रेहन अहूण प्राप्त करने तथा साथ ही इस बारे में समिति की ओर से व्यक्ति/व्यक्तियों को कागजात पर हस्ताक्षर करने के निए प्राधिकृत करने के प्रस्ताव पर विवार करना।

कार्यवाही

संकल्प किया जाता है कि ..... बैंक से वस्तुओं के बंधक/रहन के प्रति ..... में ..... तक की अवधि के लिए, केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के तहत ..... रु. की एक नकद अहूण संभाल के लिए आवेदन किया जाए। यह भी संकल्प किया जाता है कि श्री ..... और श्री ..... को अहूण व केन्द्रीय सरकार की गारंटी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ममिति की ओर से करार करने तथा सभी आवश्यक विलेख व बंध-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

समिति का नाम

(नाम रु. में)

## 1. स्वामित्वाधीन निधि

- (1) अंश-पूँजी
- (2) सावधिक आरक्षित निधि
- (3) अन्य आरक्षित निधि
- (4) योग (क)

## 2. निवेश

- (क) (1) अन्य संस्थाओं में अंश
- (2) आवधिक अथवा अन्य जमा (आरक्षित निधि, जमा को छोड़कर)
- (3) स्थार्यः परिसम्पत्तियाँ
- (4) व्यापार के बाहर निवेश को गई आरक्षित निधि

योग :

(ख) स्थार्यः परिसम्पत्तियों हेतु प्राप्त अरुण और राज-सहायता  
धाराएः :

(ग) स्वामित्वाधीन निधि में से निवेश (क—ख) (ख)

स्वामित्वाधीन निधि का निवल प्रयोज्य अंश (क—ख) पिछले वर्ष के लिए  
नियत विक्री का लक्ष्य वर्ष के दौरान की गई विक्री अगले वर्ष के  
लिए प्रस्तावित विक्री लक्ष्य

परिशिष्ट-IV

बैंक की संस्तुति का प्रारूप

संक्षेप में,

निवेशक (सी.एफ.एस.)  
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय,  
नागरिक पूर्ति विभाग,  
कृषि भवन, नई विल्ली।

विषय:—केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के अन्तर्गत संघ/सोसायटी/भंडार को रु. के लिए नकद अरुण संभा की मंजूरी के मंदंध में।

महोदय,

हम केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के अन्तर्गत संघ/सोसायटी/भंडार को रु. की नकद अरुण संभा की मंजूरी हेतु प्रस्ताव की एक प्रति साथ में भेज रहे हैं। इस बैंक ने तक की अवधि के लिए

..... सामान्य मार्जिनों पर ..... मंस्था  
 का नाम ..... को ..... रु. की; नकद श्रृणु/बंधक श्रृणु सीमा  
 मंजूर की है। समिति के पक्ष में केंद्रीय सरकार की गारंटी हमें मिल जाने के बाद 10% मार्जिन पर बंधक और/अथवा रेहन रखी  
 गई बस्तु पर समिति को नकद श्रृणु सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दे दा जाएगी।

प्रमाणित किया जाता है कि समिति श्रृणु की किश्तों का नियमित रूप से भुगतान कर रही है तथा समिति के संचालन के  
 विस्तृत कोई शिकायत नहीं है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार ..... को समाप्त  
 अवधि के लिए (मंस्था का नाम) ..... को ..... रु. की नकद श्रृणु सीमा के बास्ते केंद्रीय सरकार की गारंटी मंजूर करने की दृष्टि करें।

भवद्वाय,  
 प्रबंधक/अधिकारी

परिणाम-V

महकारी समितियों को केंद्रीय सरकार की गारंटी का सिफारिश करने समय सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा प्रस्तुत किए जाने  
 वाले द्वारे

1. सोसाइटी का नाम :

2. गत तीन वर्षों के कार्य के परिणाम :

(साथ रु. में)

वर्ष

बिंकी

निवाल लाभ/निवाल हानि

3. लेखा परिक्षा की स्थिति :

(क) अवधि जब तक संस्थान के लेखा की लेखा-परिक्षा की गई है :

(ख) यदि लेखा अद्यतन नहीं है, तो लंबित पड़े लेखाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम :

4. निरीक्षण :

(क) सरकार के अधिकारियों द्वारा सोसायटी के निरीक्षण की तारीख ।

(ख) भंडार के कार्य में देखी गई खामियां

(ग) खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदम :

5. नकद श्रृणु सीमा के लिए गांशी और गारंटी की अवधि का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की सिफारिश :

6. कृपया बताएं कि क्या तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है :

महकारी समितियों के पंजीयक

नोट:—विशिष्ट सिफारिश के अन्तर्व में प्रस्ताव को माना नहीं जा सकेगा।

## MINISTRY OF FOOD &amp; CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 1st November, 1990

## NOTIFICATION

(No. O-17011|2|89-CFS).—The Government of India notified in their notification No. O-17011|5|82-GOP dated 17th June, 1985, the continuance of the scheme of Central Government Guarantee as the fifth phase for a period from 1-4-85 to 31-3-90 to enable the Consumer Cooperatives and other cooperative institutions specified there in, to secure working capital loans from banking agencies on reduced margins during the 7th Plan period.

2. Having considered the increasing need for working capital requirements of the consumer co-operatives from banking institutions at reduced margin of 10%, it has been decided by the Government of India to operate the scheme of the Central Government Guarantee for a further period of 5 years from 1-4-1990 to 31-3-1995 (i. e., 8th Plan period).

3. All the Cooperative Societies availing of working capital loans from banking institutions under the scheme will have to pay a guarantee fee of 1% per annum.

4. In pursuance of the above decision the Government of India will consider entering into agreements in the form of Deed of Guarantee at Annexure-I, with any Apex|District Central Co-operative Bank, and bank constituted and functioning under banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970|State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act 1955, a subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks Act, 1959) in respect of secured advances made by them to :—

- (i) National Cooperative Consumers' Federation.
- (ii) All State Federation of Consumer Co-operative.
- (iii) All Wholesale|Central Consumers Co-operative Societies.
- (iv) All State level Cooperative Federation engaged in the business of consumer articles registered under any nomenclature provided that their coverage under this guarantee scheme will be restricted to their working capital requirements for distribution of consumer articles alone.
- (v) All Cooperative institutions engaged in retail business in the distribution of consumer articles registered with whatsoever nomenclature and having sales turnover of at least Rs. 20 lakhs and in case of such institutions in the cooperatively underdeveloped states (Assam, Bihar, Meghalaya, Orissa, Rajasthan, West Bengal, Manipur, Tripura, and Nagaland) having

the minimum annual sales turnover of Rs. 10 lakhs.

5. The Central Government Guarantee will be available only in respect of secured loans and advances guaranteed for specific periods before 1-4-1995 with the prior approval in writing of the Surety, against pledge or hypothecation of goods, which would include book debts securities, investments and other moveable property, to all cooperative institutions mentioned in para 4(i) to 4(v) above. The banks have to keep a margin of 10 percent only on such loans and advances. The liability under the Central Government's Guarantee in respect of any such loans and advances to any society will be limited to :

- (i) 25% of the amount of all guaranteed loans and advances actually outstanding on the books of the bank against the cooperative society on the date on which the notice of demand is issued by the bank in accordance with the terms of the agreement.

## OR

Rs. 150 lakhs (Rupees one crore & fifty lakhs) in the case of the National Cooperative Consumer' Federation, Rs. 100 lakhs (Rupees one crore) in the case of all State Level Federations including Co-operative institutions mentioned in para 4(iv) and Rs. 60 lakhs (Rupees sixty lakhs) in the case of all other cooperative institutions including those mentioned in para 4(v) irrespective of their place of business in metropolitan cities or elsewhere, whichever amount is less.

6. The guarantee in pursuance of this Notification will be available only in respect of secured loans and advances granted, for specific periods, with the prior approval in writing of the Central Government before the 1st April, 1995. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1995 and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1995 shall be covered by the guarantee. The Central Government's liability on account of this guarantee shall become determined at the close of business on the 31st March, 1995.

7. The society shall enter into an agreement with the President of India in the form provided in the First Schedule to the Deed of Guarantee, annexed hereto, undertaking:—

- (a) To pay the dues of the bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the bank while sanctioning the loan, advance or cash credit;
- (b) To carry on the business of the society diligently with a view to making profit;

- (c) To guarantee to the Central Government repayment of all moneys that may be recovered by the bank from the Central Government on account of any default on the part of the society to make payment to the bank on demand without demur;
- (d) To implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefore and recovery of their value from those responsible;
- (e) To exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions, and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery;
- (f) To ensure preparation of quarterly trading and profit and loss accounts and balance sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the society's working and submit a copy of it to the Central Government and to the State Government every quarter;
- (g) To keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State|Central Government ; and
- (h) To provide all facilities to the Central Government or any person or persons nominated by it in this behalf to examine the accounts of the society and its working.

The agreement shall be executed before the date of drawal of the money. The Bank shall not make any payment unless the signed agreement and the Letter of Consent in the form provided in the second schedule to the Deed of Guarantee are furnished.

8. The Central Government's guarantee does not extend to the interest on the loans and advances granted by banks.

9. Every bank shall continue to hold all the promissory notes and unrealised securities which may be available to the bank in respect of such loans granted by it to the society even after realisation by it in full, of the outstanding dues to it in respect of the loans and advances advanced by it under the Central Government Guarantee, till the amount reimbursed by the Central Government as guarantor is realised.

10. The bank shall obtain from the society and furnish to the Central Government, a Letter of Consent by the society as in the Second Schedule to the Deed of Guarantee, to the effect that the society agrees to:—

- (a) Continue to pay interest on any amount paid to the bank by the Central Government in pursuance of the guarantee at the same rate at which interest has been or may be charged by the bank on the loan or advance made to the society until the said amount is paid

- to or adjusted in favour of the Central Government ;
- (b) Credit or permit the bank to credit to the account of the surety all the amounts paid by or recovered from the society on account of the loan or advance, after the date on which the Central Government have reimbursed any amount to the bank in pursuance of the guarantee but after the bank's claim in respect of the loans and advances covered by the guarantee has been fully satisfied and so long as the amount paid by or recovered from the society on account of the loan interest and charges thereon have not been reimbursed by the society ;
- (c) The bank continuing to have and to exercise all the rights over the securities in favour of the bank in respect of all such loans and advances till all such claims of the Central Government are satisfied; and
- (d) The bank transferring its rights and claims under such securities to the Central Government if so required by the latter.

11. In the event of the bank being satisfied that the society has failed to make regular remittances to the bank against the advance made under the guarantee or fails to obtain the prior approval of the surety in writing for the continuance of a guarantee before its expiry, the bank will not allow further drawals by the society at reduced margin and will continue to credit all further remittances, by the society to the account of the guarantee loan till it is fully repaid.

12. The Central Government's guarantee shall not be invoked on more than one occasion by the bank in respect of a particular society. The guarantee may be invoked at any time before the 1st April, 1955. The bank shall first issue a notice of demand on the society to pay the amount to it on account of the loans and advances granted to it by the bank and guaranteed by the Surety, within thirty days of the date on which the notice asking for such repayment is served by the bank. A copy of such notice should be endorsed to the surety simultaneously. On the expiry of the period of 30 days if the society does not make payment of the amounts, the bank may issue a notice of demand on the Central Government. The Central Government shall reimburse to the bank the amount payable to it under the guarantee within a period of 90 days, from the date of receipt of the bank's notice invoking the guarantee and claiming payment.

13. The bank seeking a guarantee in pursuance of this notification shall, in the event of the Government's guarantee being invoked in the case of any loan or advance, undertake to credit to the Central Government any sums which may be realised from the society after the bank has realised from the society in full the loans and advances guaranteed by the Central Government. It shall be obligatory on the bank to take action in the above manner after the Central Government has reimbursed the amount under the guarantee.

14. The obligations of the bank referred to in the above clauses shall continue till such time as the amount reimbursed by the Central Government under the guarantee has been paid or credited to the Central Government or until the Central Government has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the bank or to the society or to waive recovery of the amount.

15. The Registrar of Cooperative Societies of the concerned State/UTs is legally and administratively the competent authority for exercising regular supervision over the working of the society and also for taking appropriate remedial measures incase any adverse features are noticed in the affairs and working of the society, or if there is any report by the bank irregard to irregular remittances by the society or any other undesirable financial features in its operation. It is clearly understood that this guarantee will be given only if the proposal is recommended by the Registrar of Cooperative Societies of the concerned State/UTs. A recommendation made by the Registrar of Cooperative Societies will be deemed to be an assurance by such Registrar that necessary steps will be the authority to enter into the prescribed agreement of the society and that appropriate remedial measures will be taken in case of any such adverse report received from the tank or from the Government of India on the affairs and working of the society.

16. Any officer of the rank of Director/Deputy Secretary and above in the Ministry of Government of India dealing in Consumer Cooperatives, New Delhi duly nominated by the competent authority will be the authority to enter into the prescribed agreement of guarantee with the banks for the Central Government Guarantee in pursuance of this notification. All banks referred to in the notification are advised to contract the officer incharge of the Guarantee and operation in the Ministry as indicated above in case they wish to avail themselves of the facility provided by the Central Government.

Dr. P. K. MONGA, Director

#### ANNEXURE

#### DEED OF GUARANTEE

This deed of Guarantee entered into on the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ between the President of India (Hereinafter called "the Surety") of the one part and the \_\_\_\_\_ a bank constituted and functioning under the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970|State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955| \_\_\_\_\_ (Name of the Bank), a subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959|a Cooperative Society registered under \_\_\_\_\_ and having its \_\_\_\_\_ office at \_\_\_\_\_ of the other part witnesseth as follows :—

In consideration of the Bank making loans and advances to \_\_\_\_\_ (hereinafter

called the Society) at the latter's request, after relaxing margins which the Bank but for this guarantee might have normally kept, the Surety hereby guarantee to the Bank to the extent hereinafter provided the repayment of loans and advances by the society to the Bank subject to their terms and conditions hereinafter mentioned :—

1. The Surety's guarantee will be available only in respect of any secured loan or advance granted for specific periods to the society with the prior approval in writing of the Surety by the Bank before the 1st April, 1995 against the pledge or hypothecation of goods, which would include book debts, securities investments and other movable property. The Bank agrees to keep a margin of only 10% against such loans and advances.

2. The Surety's liability in respect of any loan or advance granted as above to the said society shall not at any time exceed :—

(i) twenty-five per cent of the amount of the guaranteed loans and advances actually outstanding on the books of the Bank against the society on the date on which the notice of demand on the Surety is issued by the Bank in accordance with the provisions of the clause (3) hereof :—

OR

(ii) Rs. \_\_\_\_\_ lakhs only, whichever amount is less.

3. The Bank may invoke the Surety's guarantee at any time before the 1st of April, 1995 in the manner hereinafter specified, namely :—

(i) The Bank shall first issue a notice of demand on the society to pay the amount due to it on account of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, within thirty days of the date on which the notice asking for such repayment is served by the Bank. A copy of such notice should be endorsed to the Surety simultaneously.

(ii) If on the expiry of the period of 30 days, as aforesaid, the society does not make payment of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, the Bank shall issue a notice of demand on the Surety.

(iii) The Bank shall while invoking Surety's guarantee, furnish to the Surety :—

(i) details of the goods, against which loan or advance in respect of which the guarantee is invoked has been granted.

(ii) the market value of the said goods, and

(iii) the amounts outstanding against the society as a :—

(a) the date on which the notice asking for repayment was issued to the Society by the Bank; and

(b) the expiry of thirty days of the date of notice asking for repayment, and

(iv) The Surety shall reimburse to the bank the amount due to it to the extent provided in this guarantee within a period of 90 days from the date of receipt by the Surety of the Bank's notice invoking the guarantee and claiming payment.

4. The guarantee herein contained shall be enforceable against, the Surety notwithstanding that any securities that the Bank may obtain from the Society shall be outstanding or unrealised.

5. The society shall enter into an agreement with the President of India in the form annexed in the First Schedule to the deed of Guarantee, undertaking :—

- (a) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan, advance to cash credit;
- (b) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit;
- (c) guaranteeing to the Central Government repayment of all monies that may be recovered by the Bank from the Central Government on account of any default on the part of the society to make payment to the Bank, on demand without demur;
- (d) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;
- (e) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery ;
- (f) to ensure preparation of quarterly trading profit & loss accounts and balance sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the Society's working and submit a copy of it to the Surety every quarter;
- (g) to keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State|Central Governments; and
- (h) to provide all facilities to the Surety on any person or persons nominated by it in this behalf to examine its accounts and its working;

The Bank shall not make any payment to the Society unless the agreement in the proforma in the First Schedule and the letter of Consent as in the Second Schedule to the Deed of Guarantee are furnished to it duly executed by the parties.

6. The bank shall agree, in consideration of the guarantee which is available to it from the Surety:—

- (a) to pay or credit to the account of the Surety any amount which will be realised from the society after the date on which the Surety has reimbursed the amount guaranteed, after it has realised in full the loans and advances guaranteed by the Surety;
- (b) to retain all the promissory notes or unrealised securities which may be available to the Bank in respect of the loan granted by it to the society even after realisation by it in full of the outstanding due to it, till the amount reimbursed by the Surety is realised;
- (c) to obtain from the Society and to furnish to the Surety, a letter of consent in the form provided in the Second Schedule hereto ;
- (d) if so required by the Surety, to transfer all such promissory notes or securities to the Surety, and/or his nominee, after the Bank has realised in full the outstanding due to it, but if the Surety has not been reimbursed the amount paid by it, and
- (e) to obtain from the Society and furnish to the Surety an agreement in the form provided in the First Schedule to the Deed of guarantee annexed hereto, as provided in the Clause 1 hereto.

7. The Surety's guarantee will not extend to the interest on the loans and advances sanctioned to the Society.

8. The obligation of the Bank in pursuance of the provisions of clause (6) shall continue until such time as the amount reimbursed by the Surety has been paid or credited to the Surety, or until the Surety has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the Bank or to the Society or to waive the recovery of the amount.

9. The Surety's guarantee shall not be invoked on more than one occasion by the Bank in respect of the society and if or after the Surety's guarantee has been invoked, any loan or advance is granted to the society on whose behalf any amount has been paid to the Bank by the Surety, any such loan or advance shall be at the Bank's own risk and the Surety will have no liability on account of such further loan or advance.

10. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1995 and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1995 will be guaranteed by the Surety. The Surety's liability shall become determined at the close of business on the 31st March, 1995.

11. The Surety shall be entitled to obtain from the Bank such information and returns relating to the loans and advances in respect of which this guarantee is available to the Bank and the Bank shall furnish such information or return at such intervals and in such manner as may be specified or required by the Surety.

12. If there is any difference or dispute between the parties hereto, arising out of or in connection with this agreement or concerning the meaning or interpretation thereof or otherwise howsoever in relation to his agreement, the same shall be referred to the sole arbitration of the person holding for the time being the post of Additional Legal Adviser (Arbitration) to the Government of India and decision of the said officer shall be final and binding on both the parties. It will be no objection that the arbitrator is a Government servant, that he had to deal with the matters to which this guarantee relates or that, in course of his duties as a Government servant, he has expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The provisions of the Arbitration Act, 1940 or any statutory modification or re-enactment thereof shall apply to such arbitration. The arbitration proceedings shall be held at such place as the Arbitrator may decide. The Arbitrator shall be entitled with the consent of the parties, to extend from time to time, the time for making the award.

13. The Stamp duty, if any, payable on this Deed of Guarantee shall be borne by the President of India.

14. In witness whereof the Surety and the Bank have caused these presents to be duly executed the day and year above mentioned.

Signature of the Officer Incharge  
(Guarantee and Operations)

In the Government of India, in the Ministry dealing in Consumer Coop. acting in the premises for and on behalf of the President of India. In the presence of :—

Witnesses :

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

#### FIRST SCHEDULE

#### AGREEMENT

This agreement made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ between \_\_\_\_\_ the President of India (hereinafter called "The Central Government" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successors in Office and assigns) of the one part and \_\_\_\_\_ a cooperative society registered under the \_\_\_\_\_ and having its registered [central] head office at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "The Society" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its executors, administrators, representatives and permitted assigns and successors) on the other part, witnesseth as follows :—

In consideration of \_\_\_\_\_ Bank making loans, advances, cash credit limit and other banking facilities and accommodations to the Society, inter alia on the Central Govt. guaranteeing repayment of a part of the loan and advance made to the society by the Bank, the Society hereby undertakes to the Central Govt. :—

- (i) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan advance or cash credit;
- (ii) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit;
- (iii) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible;
- (iv) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery;
- (v) to ensure preparation of quarterly trading and profit and loss accounts and balance sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the society's working and submit a copy of it to the Central Government and also to the State Government every quarter;
- (vi) to keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State/Central Govt.; and
- (vii) to provide all facilities to the Central Govt. or any person or persons nominated by it in this behalf to examine the accounts and its working.

2. The Society guarantees to the Central Govt. repayment of all monies that may be recovered by the Bank from the Central Govt. on account of any default on the part of the Society on demand without demur.

3. All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this agreement, excepting Clause 2 above shall be referred to the Sole Arbitration of the person holding the post of Additional Legal Adviser (Arbitration) Govt. of India. It will be no objection that the arbitrator is a Govt. servant or that he had expressed views in all or any of the matters in dispute or difference. The provisions contained in the Indian Arbitration Act shall apply to such arbitrations. The award of the Arbitrator shall be final and binding on both the parties.

Signed by (name & designation)  
for and on behalf of the  
President of India.

Witnesses :

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Signed by the Authorised representative(s) of the Society  
(name and designation)

SECOND SCHEDULE  
LETTER OF CONSENT

To

1. \_\_\_\_\_ Bank

2. President of India

In consideration of the President of India (hereinafter referred to as the President) having agreed to guarantee the repayment of a part of the loans and advances made to the (Name of the Society) \_\_\_\_\_ by the (Name of Bank) \_\_\_\_\_

(hereinafter referred to be "the Bank"), we hereby agree that any promissory note and any security by way of pledge, or hypothecation of goods, which would include book debts, securities, inventories and other moveable property, that we have given and may give to Bank in connection with such loans and advances shall be subsisting and may be retained by the bank, notwithstanding the fact that in pursuance of the guarantee given to the Bank by the President, the President may have made good any deficit in our account.

We further agree:—

- (a) to continue to pay interest on any amount paid to the Bank by the President in pursuance of the President's guarantee at the same rate at which interest has been or may be charged by the Bank on the loan or advance made to us till the said amount is paid to or adjusted in favour of the President;
- (b) to credit or to permit the Bank to credit to the account of the Society of all the amounts paid by or recovered from us on account of the loan or advance, after the date on which the President has reimbursed any amount to the Bank in pursuance of the President's guarantee but after the Bank's claim in respect of the loans and advances covered by the President's guarantee has been fully satisfied and so long as the amounts reimbursed by the President together with the interest and charges thereon have not been reimbursed by us;
- (c) to the Bank continuing to have and to exercise all the rights over the securities in favour of the Bank in respect of all such loans and advances till all such claims of the President as are referred to in clause (b) are also satisfied; and
- (d) to the Bank transferring its rights and claims under such securities to the President, if so required by or on his behalf.

Witnesses :

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Signature by the Authorised  
representative(s) of the  
Society (Name & Designation)

## ANNEXURE-II

Procedure for submission of proposed for sanction of Central Government Guarantee for obtaining working capital loan at reduced margin from the Nationalised Cooperative Banks under the Central Government Guarantee Scheme circulated vide notification No. O-17011/2/89-CFS dated 1-11-90

The institution seeking Central Government Guarantee shall have to submit proposed with the following information and documents :—

- (i) Particulars of the institution in the prescribed form (Appendix-I) alongwith the reasons if there is any shortfall in its sales and profitability during any particular year.
- (ii) Resolution of the Board of Directors (Appendix-II) not earlier than three months from the date of application indicating the decision of the institution to obtain the working capital loan from a particular bank under Central Government Guarantee and also authorising the persons to sign necessary declared documents.
- (iii) Agreement form as given at first schedule of the notification duly signed by the authorised persons and two witnesses with full address.
- (iv) Letter of consent as given at a second schedule of the notification duly signed by the authorised persons alongwith two witnesses with full address.
- (v) Audited/proforma statement of accounts viz. Trading and Profit & Loss accounts and balance sheet—for last 4 cooperative years of which atleast audited statements of Accounts should be for two years alongwith proforma account for the subsequent half year/quarter. The certificate as regards completion of audit need to be incorporated.
- (vi) In case the institution which has incurred loss during any one of the four preceding years including the current one, detailed reasons for the loss as well as the specific steps initiated by the society to regain profitability may be indicated in above note.
- (vii) A copy of the by laws of the society.
- (viii) A certificate of maximum borrowing limit of the society.
- (ix) A statement indicating the disposable part of owned funds at the end of latest cooperative year as per Appendix-III.

2. Proposal on the above line is to be prepared in quadruplicate atleast three months in advance before the date from which the guarantee is required and one copy to be submitted to the financing bank for sanction of the cash credit loan, another copy to be submitted to the State Registrar of Cooperative

Societies for sending his recommendations to the Government of India and another copy to be sent to the Government of India as an advance copy.

The guarantee fee of 1% per annum will have to be sent through a Demand Draft drawn in favour of the PAO, Department of Civil Supplies payable at New Delhi alongwith the application.

4. On receipt of the application, after considering the proposal, the bank shall recommend the case to the Government of India in the proforma given at Appendix-IV, while recommending the case the bank's attention is particularly drawn to para 10 of the scheme.

5. On receipt of another advance copy the Registrar Coop. Societies will recommend the case to the Government of India alongwith the informaion as per proforma at Appendix-V. In this connection his attention is drawn to para 14 of the scheme.

6. The recommendations of the financing bank as well as the Registrar Cooperative Societies should be sent to this Ministry atleast one month in advance of the date from which the Central Government Guarantee is required.

7. Incomplete application will not be entertained

#### Appendix—I

Particulars to be furnished by the Cooperative Institution applying for working capital loan from financing bank under Central Government Guarantee Scheme. (To be based on the latest figure)

1. Name and full address of the Society.
2. Date of registration, alongwith date of commencement of operations.

3. (a)

Number of members	Amount of Share Capital
-------------------	-------------------------

(Rs. in lakhs)

- (i) Individuals
- (ii) Societies/Institutions
- (iii) Government
- (iv) Total

(b) Composition of Board of Directors.

- (i) Elected Members
- (ii) Nominated Members
- (iii) Total:

4. Borrowing powers:

- (a) Quote the number of Byelaws/Rules of the Society regarding powers to borrow from the bank and the overall borrowing limits approved by the Registrar of Coperative Societies.
- (b) A certificate in writing from the management of the Society should be furnished indicating the borrowing limit of the society.

5. A resolution authorising the office bearers of the society to obtain loans and advances from the bank under Central Government Guarantee scheme and also to sign the documents on behalf of the society in this respect should be passed by the Board of

(A proforma at appendix-II)

Directors/Committee of Management and a certified copy thereof should be attached with the application. (indicate the names of the persons)

6. Justification for cash credit limit applied for, which should inter-alia, contain information on following aspect:

Sl. No.	Commodities/group of commodities handled by the society	Anticipated Annual Sales (Rs. in lakhs)	Stock turn (Annual Sales — (Opening Stock plus Closing Stock)
---------	---	---	---

7. Particulars of credit facilities required :

(a) Cash credit limit against:

- (i) Pledge of goods.
- (ii) Hypothecation of goods.

(b) The period for which the advance is required.

8. Total owned funds and disposable part of owned funds. (as per proforma at appendix-III)

9. No. of branches	In Rural areas	In slum areas and areas populated by weaker sections.	In other areas of society
(i) Deptt. Stores			
(ii) Exclusive Fair price Shop			
(iii) Others.			
(iv) Total			

10. Sales during last three Coop. Years.

(Rs. in lakhs)

Year	Controlled Commodities	Non-Controlled Commodities	Essential Items	Total
(i)				
(ii)				
(iii)				

11. Details of borrowings at the end of last Coop. Year.

Agency	Purpose	Total Amount sanctioned	Maximum borrowing during the year	Outstanding at the end of the year
--------	---------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

(i) Government

- (a) For Specific Project
- (b) For working capital

- (ii) From financing Banks
- (iii) From other sources  
(Please specify)
- (iv) Total

12. Last two audited balance sheets and proforma balance sheets for subsequent years till the end of the last cooperative year (A copy of the audited accounts, trading, profit and loss accounts and balance sheets to be attached). Indicate the authority who had audited the accounts.

13. Audit classification awarded by the Registrar.

14. If the store is currently running in loss, reasons therefor and details of the remedial measures adopted, along with the programme of action for improving the functioning and economic viability of the society (To be furnished in a separate note to be attached to this proforma).

15. Details of Guarantee facilities availed/Rehabilitation assistance received by the Institution till today.

16. Reasons for failure to repay loans/installments to financing bank, if any.

17. Details of Demand Draft paying 1% Guarantee Fee.

Signature of the President/  
General Manager/Secretary of  
the Society.

#### Appendix—II

Extract from the proceedings of the meeting of the Board of Directors held on

Agenda	Proceedings
<p>To consider the Proposal for obtaining a cash credit/hypothecation loan of Rs. _____ from _____ Bank under the Central Government Guarantee Scheme and also to authorise the person/persons to sign the documents on behalf of the society in this regard.</p>	<p>It is resolved to apply to _____ bank for a cash credit limit against pledge/hypothecation of goods for Rs. _____ for the period from _____ to _____ under Central Government Guarantee Scheme. It is further resolved that Shri _____ and Shri _____ are authorised to enter into agreement and to sign and execute all necessary deed and bonds in this connection on behalf of the society for obtaining loan and sanction of Central Government Guarantee.</p>

Name of the Society

(Rs. in lakhs)

1. Owned funds
  - (i) Share capital
  - (ii) Statutory Reserves
  - (iii) Other reserve funds
  - (iv) Total (A)
2. Investment
  - (a) (i) Shares in other Institutions
  - (ii) Fixed or other deposits  
(excluding reserve funds deposits).
  - (iii) Fixed Assets
  - (iv) Reserve funds invested outside the business.

Total:
- (b) Less loans and subsidies received for fixed Assets.

---

(c) Investment from owned funds (a—b) (B)

---

Net disposable part of owned funds (A—B)

Sales target fixed for the preceding year

Sales achieved during the year

Sales target proposed for the next year

## SAMPLE RECOMMENDATION OF THE BANK

To

wif[

The Director (CFS)  
 Ministry of Food & Civil Supplies  
 Department of Civil Supplies  
 Krishi Bhawan  
 New Delhi

Subject: Sanction of cash credit limit for Rs. \_\_\_\_\_ under the Central Government Guarantee Scheme to \_\_\_\_\_ Federation/Society /Store—Regarding

Sir,

We are forwarding here with a copy of the proposal for sanction of cash credit limit of Rs. \_\_\_\_\_ under Central Government Guarantee Scheme received from \_\_\_\_\_ Society. The Bank has sanctioned a cash credit/hypothecation limit of Rs. \_\_\_\_\_ to the (Name

of the Institution) for period upto on normal margins. The society will be allowed to avail the cash credit facilities against pledge and/or hypothecation of goods at 10% margin after the receipts of the Central Government Guarantee to us in favour of the Society.

It is certified that the Society is repaying the loan instalments regularly and there is no complaint against the working of the society.

It is, therefore, requested that Government of India may please sanction Central Government Guarantee for a cash Credit limit of Rs. to (Name of the Institution) for the period ending.

Yours faithfully,

Manager/Agnt

Appendix—V

Particulars to be furnished by the Registrar of Cooperative Societies while recommending Central Government Guarantee in favour of Consumer Cooperatives.

(Rs. in lakhs)

1. Name of the Society
2. Working Results for the last three years.

	Year	Sales	Net Prot/Net loss
--	------	-------	-------------------

3. Position of Audit:

- (a) The period upto which the accounts of the institution have been audited.
- (b) If audit is not upto date, steps taken/ proposed to be taken for ensuring completion of pending audit.

4. Inspection

- (a) Date of which the Society was last inspected by officers of the Government.
- (b) Shortcomings, if any noticed in the working of the Store.
- (c) Steps taken to remedy the shortcomings.

5. Recommendation of the State Government specifying the extent of cash credit limit and the period for which guarantee may be given.

6. Indicate whether the quarterly progress Reports are being submitted regularly.

Registrar Cooperative Societies

N.B. In absence of specific recommendations the proposal may not be agreed to.